

प्र० निरा०/अर्था०/कू-सा०/2017/3492

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल कार्यालय सर्किट कोटि रोपा म०प्र०



धन्नु कुशवाहा आत्मज द्वारा उम् 42 वर्ष निवासी ग्राम सेमरा थाना व तहसील

मानपुर उमरिया म०प्र० ..... आवेदक

बनाम

रामचरण आत्मज पोकड़या का छी साक्षि छड़ौर थाना व तहसील मानपुर

जिला उमरिया म०प्र० ..... आवेदक

कृपयोग्ये श्री रामलोपा पा। 25-7-17  
द्वारा  
मूल

कानूनी अफ बोर्ट  
राजस्व मण्डल म०प्र० लालिया  
(सर्किट कोटि) रीवा

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश श्रीमान राजस्व  
निरीक्षक वृत्त अनपुर तहसील मानपुर जरिये, प्रकरण  
क्र. 35 अ-12/ 2016-17 मे पारित आदेश  
दिनांक 28/7/17 जिसमे बिना विचार किये  
आपत्ति निरस्त किया धारा 50 म०प्र० भूराजस्व  
संहिता 1959 है,

मान्यवर,

आवेदक निगरानी करा विनम्र निवेदन करता है कि:-

१।- यहकि राजस्व निरीक्षक तहसील मानपुर का आदेश कानूनन वाक्यातान  
त्रुटि पूर्ण है।

२।- यहकि पट्टवारी तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन चैन  
सर्व मे सिद्धान्त तथा नियमो के अनुकूल नहीं है। सर्व का नियमाघव है कि किसी  
खसरा नम्बर को पैमाइस करने के लिये एक मुस्तकिल बिन्दू को धारो तरफ से नापकर  
सत्यापित करना चाहिये कि नम्बर के अनुसार मौके पर भी वहसही स्थान पर है।

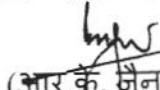
३- यहकि ब्लॉक कील्ड बुक देखने से पताचला है कि नाप करने से स्फूर्ति ए से  
बी. , बी. , से सी. , सी. , डी. आदि तक नाप करने का वर्जन है किन्तु यह कहीं -

२  
**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

प्रकरण क्रमांक- तीन/निग./उमरिया/भू.रा./2017/3492

**धन्न कुशवाहा विरुद्ध रामचरण**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२-०१-२०१९	<p>१. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>२. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>३. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त अनूपपुर, जिला-उमरिया के प्रकरण क्रमांक ३५/अ-१२/२०१६-१७ में पारित आदेश दिनांक २८-०७-२०१७ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>४. म.प्र. भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा १२९ में किये गये संशोधन वर्ष २०१८ के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं।</p> <p>५. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २५-०३-२०१९ को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।</p>	 (आर.के. जैन) २२.०१.१९ सदस्य